नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 123
दि. 05.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सियासी संग्राम महाभियोग की मांग से गरमाई राष्ट्रीय राजनीति

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष सुधार अभियान से शुरू हुआ विवाद अब देश की संवैधानिक संस्थाओं की साख और निष्पक्षता पर बहस का रूप ले चुका है। इस बहस के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिनके खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाभियोग लाने की मांग कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ममता की इस मांग को अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) जैसे विपक्षी दलों का समर्थन मिलने लगा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और सड़कों दोनों पर बड़ी राजनीतिक टकराहट का कारण बन सकता है। विवाद की जड़ पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची सुधार के विशेष अभियान में बताई जा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस अभियान के जरिए बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया न केवल पक्षपातपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला भी है। ममता बनर्जी के अनुसार, किसी नागरिक का वोट छिनना उसके संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने जैसा है और यही कारण है कि उन्होंने इस मुद्दे को केवल राज्य की राजनीति तक सीमित न रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है।

ममता बनर्जी ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन यह बैठक भी विवाद का कारण बन गई। ममता का आरोप है कि बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया अहंकारी और असंवेदनशील था। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्होंने बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसी के बाद ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए अन्य विपक्षी दलों से समर्थन मांगा।

ममता की इस पहल को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलना विपक्षी एकजुटता का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह एक गंभीर और प्रासंगिक मुद्दा है, जिस पर पूरा विपक्ष मिलकर फैसला करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस ने इस विषय में कांग्रेस से संपर्क किया है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस का यह रुख इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी आमतौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे कदमों में बेहद सतर्क रहती है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि

भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट का अधिकार छिनना नागरिकता पर सवाल खड़े करने जैसा है और अगर लोग अब नहीं जागे तो धीरे-धीरे उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ खड़ी है।

वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके इस रुख को राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग तरह से देखा जा रहा है। कुछ इसे रणनीतिक चुप्पी मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि कांग्रेस अभी इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने से पहले सभी कानूनी और राजनीतिक पहलुओं को तौलना चाहती है।

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। प्रियंका का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में और विपक्ष शासित राज्यों में चुनाव आयोग का रवैया अलग-अलग नजर आता है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर उन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो पारंपरिक रूप से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी द्वारा इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाना एक सही कदम है और उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखेगी।

इस पूरे विवाद ने महाभियोग की प्रक्रिया को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही होती है। इसके लिए साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता को आधार बनाना जरूरी होता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसे पारित कराने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया बेहद कठिन और राजनीतिक सहमति पर निर्भर मानी जाती है।

इस सियासी घमासान के बीच एक और असाधारण दृश्य सामने आया, जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के साथ बैठकर बंगाल में चल रहे विशेष मतदाता सूची सुधार अभियान के मुद्दे पर खुद दलीलें देती नजर आईं। यह पहली बार था जब कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील बहस करता दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर न्याय नहीं मिल रहा है और उनके सवालों का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है।

सोनम वांगचुक की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र से हिरासत पर पुनर्विचार का संकेत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। जलवायु कार्यकर्ता और सामाजिक चिंतक सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए हिरासत की समीक्षा पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब वांगचुक पिछले कई महीनों से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत के सामने मौजूद स्वास्थ्य रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है और इसमें सुधार के संकेत नहीं दिखते। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि वे केवल कानूनी दलीलों तक सीमित न रहें, बल्कि एक संवैधानिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी इस मामले पर पुनर्विचार करें। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि न्यायालय

केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि न्यायिक विवेक और मानवीय सरोकार भी उसके निर्णयों का अहम हिस्सा होते हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि वांगचुक की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट पहले अदालत के सामने आई थी, उसमें भी उनकी सेहत को लेकर गंभीर संकेत थे और समय के साथ स्थिति और बिगड़ सकती है।

सोनम वांगचुक वर्तमान में जोधपुर केंद्रीय कारागार में निरुद्ध हैं। उनके खिलाफ 26 सितंबर 2025 को हिरासत का आदेश पारित किया गया था, जिसे बाद में 3 अक्टूबर 2025 को अनुमोदन मिला। केंद्र सरकार का पक्ष है कि यह हिरासत कानून के तहत पूरी तरह वैध है और इसे अब तक किसी सक्षम मंच पर चुनौती नहीं दी गई है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि वांगचुक की गतिविधियों का संबंध पिछले वर्ष लेह में हुई हिंसक घटनाओं से है, जिनमें चार लोगों की मौत हुई थी और 161 से अधिक लोग घायल हुए थे। केंद्र का दावा है कि इन घटनाओं में उनकी भूमिका को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास ठोस इनपुट हैं। हालांकि, वांगचुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हिरासत का आदेश न केवल कानून की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन करता है। उन्होंने अदालत को बताया कि जिस सामग्री के आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया गया, वह चुनिंदा और अधूरी थी तथा प्राधिकारी को पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई। सिब्बल ने यह भी दलील दी कि एक शांतिपूर्ण पर्यावरण कार्यकर्ता को इस तरह हिरासत में रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह इस मामले को केवल तकनीकी आधार पर नहीं देख रही है। पीठ ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की सेहत लगातार गिर रही है और वह लंबे समय से हिरासत में है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी स्थिति की समीक्षा करे। अदालत ने केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई कि वह संवेदनशीलता दिखाए और हिरासत जारी रखने की आवश्यकता पर दोबारा विचार करे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि कोर्ट की टिप्पणियों और सुझावों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

अमृत भारत स्टेशन योजना से बदली महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों की सूरत, 17 स्टेशनों का कायाकल्प पूरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना महाराष्ट्र में तेज़ी से आकार ले रही है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक पांच उपनगरीय स्टेशनों सहित कुल 17 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और कायाकल्प का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन स्टेशनों में आमगांव, चंदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहद, वडाला रोड, बारामती और नंदुरा शामिल हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिवसेना (शिंदे) के सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

रेल मंत्रालय के अनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य केवल इमारतों को नया रूप देना नहीं है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, सुगम आवागमन, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक तकनीक से लैस स्टेशन उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां रोज़ाना लाखों यात्री लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर करते हैं, इन स्टेशनों का पुनर्विकास विशेष महत्व रखता है। उपनगरीय स्टेशनों का कायाकल्प होने से मुंबई महानगर क्षेत्र में रोज़ाना सफर करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलने लगा है। रेल मंत्री ने संसद को बताया कि मुंबई का ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी इस योजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्विकास की ओर बढ़ रहा है। सीएसएमटी के लिए पुनर्विकास को स्वीकृति दी जा चुकी है और लंबी दूरी के नोड भवन, नए कॉनकोर्स और पैदल पार पुल संख्या एक और दो के लिए नींव का कार्य शुरू हो गया है। यह स्टेशन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की रेलवे विरासत का प्रतीक है, ऐसे में इसके पुनर्विकास को आधुनिकता और विरासत के संतुलन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुंबई महानगर क्षेत्र के अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेज़ी से चल रहा है। दिवा स्टेशन भवन में सुधार, नया प्रवेश द्वार बनाने और कल्याण व मुंबई छोर पर फुटओवर ब्रिज के विस्तार व सुधार जैसे कार्य जारी हैं। इसके अलावा मुंब्रा, टिटवाला, विक्रोली, चर्नी रोड, मालाड, कल्याण, दादर, ठाणे और पुणे जैसे व्यस्त स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण यहां सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे स्टेशनों में आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, बेहतर रोशनी, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं, पार्किंग की बेहतर व्यवस्था और स्थानीय संस्कृति को दर्शाने वाले डिजाइन को प्राथमिकता दी जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है ताकि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो।

रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि देशभर में होल्डिंग या प्रतीक्षा क्षेत्र के निर्माण के लिए 76 स्टेशनों की पहचान की गई है। इनका उद्देश्य त्योहारों, छुट्टियों और पीक सीजन के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना है। इनमें महाराष्ट्र के सात प्रमुख स्टेशन शामिल हैं, जिनमें मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, नगर, नाशिक रोड, पुणे स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर बड़े प्रतीक्षा क्षेत्र विकसित होने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भीड़ से राहत मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

महाराष्ट्र में स्टेशन पुनर्विकास को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इसे एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड और शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय दीना पाटील द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार लगातार निवेश बढ़ा रही है। उनका कहना था कि रेलवे स्टेशन केवल यात्रा के स्थान नहीं, बल्कि शहरों की पहचान और विकास के केंद्र भी होते हैं।

लोकसभा में अभूतपूर्व टकराव, हंगामे की भेंट चढ़ा प्रधानमंत्री का जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को लोकसभा ऐसा दृश्य देखती नजर आई, जिसने संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के तीखे विरोध और लगातार हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुप्रतीक्षित जवाब एक बार फिर टल गया। दिन की कार्यवाही तीन बार स्थगित होने के बाद शाम तक हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पूरे सदन को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों के आसन तक जा पहुंचा, जिसे संसदीय इतिहास में एक असाधारण और असहज स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। सुबह से ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के तेवर तीखे थे। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर 'वेल' में आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उनका आरोप था कि सरकार गंभीर मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है और प्रधानमंत्री संसद में जवाब देने से बच रहे हैं। बार-बार अपील के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा, तो कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। यह सिलसिला दिन में तीन बार दोहराया गया, लेकिन हर बार सदन दोबारा शुरू होते ही शोर और नारेबाजी और तेज हो गई।

शाम होते-होते हालात ने ऐसा मोड़ ले लिया, जो संसद के इतिहास में शायद ही पहले देखा गया हो। कांग्रेस की महिला सांसद बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लेकर न सिर्फ 'वेल' में पहुंचीं, बल्कि उसे पार करते हुए सीधे सत्ता पक्ष की सीटों और मंत्रियों के आसन की ओर बढ़ गईं। यह दृश्य कैमरों में कैद हुआ और देखते ही देखते संसद परिसर के भीतर हलचल मच गई। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बिना देर किए सदन को स्थगित करने का फैसला लिया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सदन के भीतर तनाव खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि के नेतृत्व में महिला सांसद सत्ता पक्ष की सीटों के पास खड़ी रहीं और सरकार पर आरोपों की बौछार करती रहीं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू, अश्विनी वैष्णव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। शब्दों की तल्खी इतनी बढ़ गई कि माहौल हाथापाई की कगार पर पहुंचता दिखा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे और स्थिति को संभालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन विवाद तब और गहरा गया जब विपक्षी सांसद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों का विरोध करते हुए उनके और करीब जाने लगे।

स्थिति की नाजुकता को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने संयम का रास्ता अपनाने की कोशिश की। वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं ने अपने सांसदों को पीछे हटने और किसी भी तरह के सीधे टकराव से बचने की सलाह दी। पार्टी के भीतर यह संदेश साफ था कि विपक्ष की उकसावे वाली रणनीति में फंसने के बजाय हालात को शांत रखना ज्यादा जरूरी है। हाथापाई या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भाजपा नेताओं ने अपने सांसदों को सदन से बाहर जाने तक की सलाह दी, ताकि माहौल और न बिगड़े। इसी बीच यह भी सामने आया कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को पहले से अंदेशा था कि विपक्ष का प्रदर्शन सामान्य विरोध से आगे बढ़ सकता है और कोई अप्रिय स्थिति बन सकती है। इसी आशंका के चलते यह तय किया गया था कि प्रधानमंत्री केवल तभी सदन में आएंगे, जब हालात नियंत्रण में हों। लेकिन जिस तरह सांसद बैनर लेकर मंत्रियों के आसन तक पहुंच गए, उसे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी चूक माना जा रहा है।

संसद के भीतर इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने जानबूझकर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास किया। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार बहस से भाग रही है और जबरन उनकी आवाज दबाई जा रही है, इसलिए उन्हें सड़क से लेकर संसद तक विरोध करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह साफ है कि संसद का कामकाज पूरी तरह ठप हो चुका है।

अब सबकी निगाहें गुरुवार पर टिकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि यदि लोकसभा में हालात सामान्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे। लेकिन अगर हंगामा जारी रहता है, तो प्रधानमंत्री पहले राज्यसभा में अपना वक्तव्य दे सकते हैं, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस लगभग पूरी हो चुकी है। इस बीच यह भी संकेत मिले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार को सदन के भीतर सांसदों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कुछ सख्त कदमों की घोषणा कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी सदस्य इस तरह नियमों की सीमाएं न लांघ सके। लोकसभा में बुधवार को जो कुछ हुआ, उसने यह सवाल छोड़ दिया है कि क्या संसद संवाद और सहमति का मंच बनेगी या राजनीतिक टकराव का अखाड़ा। जिस सदन में देश की नीतियों और भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए, वहां लगातार हंगामा और अवरोध लोकतंत्र की सेहत के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा रहे। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस टकराव से कोई सबक लेते हैं या संसद की कार्यवाही इसी तरह गतिरोध की भेंट चढ़ती रहेगी।

संपादकीय

पर व्यापार समझौते में अमेरिकी पलड़ा भारी

यह सुखद ही है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाये गए भारी-भरकम पचास फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देने की बात कही जा रही है। दलील दी जा रही थी कि भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने के एवज में पच्चीस फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। कुछ वैश्विक व्यापार के जानकार मानते हैं कि यह व्यापार समझौते को अमेरिका के पक्ष में लाने के लिये दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा ही था। लेकिन जिसके आगे भारत ने जल्दी से घुटने नहीं टेके थे। अब कहा जा रहा है कि टैरिफ के पचास फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से भारत ने राहत की सांस ली है। यह भारत के रत्न, आभूषण, वस्त्र और परिधान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिये सुखदकारी खबर है, जो बीते साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद से ही संघर्षरत रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से प्रतीक्षित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सिरे चढ़ने के करीब है। आशंका जताई जा रही है कि यह समझौता अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। हालांकि, इस समझौते से जुड़े व्यापक विवरण का अभी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ, रक्षा संबंधी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार से जुड़े उपकरण और विमानों की खरीद बढ़ाएगा। अमेरिका के नीति-नियंता दलील देते रहे हैं कि यह व्यापार समझौता उसके व्यापार घाटे को कम करने और कथित रूप से भारत को 'अनुचित लाभ' से वंचित करने की डोनाल्ड ट्रंप की मंशा के अनुरूप ही है। यह समझा जा रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका ने दबाव डालकर भारत को रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिये बाध्य कर लिया है। हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। इसी तरह व्यापार बाधाओं को कम करने में भी कुछ वक्त लग सकता है।

वैसे रूस से तेल खरीदने पर रोक के संकेत तब मिलने लगे थे, जब भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करनी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी ओर रूस से होने वाली कम आपूर्ति से उपजी परिस्थितियों के मुकाबले के लिये भारत ने पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ़ा दिया था। वैसे इस बाबत चिंता की बात तब उत्पन्न हुई थी जब अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने कहा था – 'व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा, कीमतों में वृद्धि करेगा और अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में नकदी का प्रवाह बढ़ाएगा।' ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मोदी सरकार डेयरी और कृषि क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिये भारत के बाजारों को खोलते हुए घरेलू किसानों के हितों की रक्षा कर पाएगी? यह जानते हुए भी कि भारत में कृषि व किसान राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा है। वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लगातार दबाव व 'या तो मेरी बात मानो या फिर रास्ता छोड़ दो' वाले रवैये ने नई दिल्ली को कई रियायतें देने और समझौते करने के लिये मजबूर कर दिया है। निस्संदेह,यह एक हकीकत है कि व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका का पलड़ा भारी बना हुआ है। जिससे भारत की सौदेबाजी करने की क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता बनाये रखने की क्षमता को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धियों मसलन इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश आदि पर अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाए जा रहे हैं। हालांकि, चिंता इस बात को लेकर भी जतायी जा रही है कि भारत ने ट्रंप को मात देने का एक अवसर खोया भी है। वैसे यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका की सारी नीतियां अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पर ही खत्म हो जाती हैं। खासकर ट्रंप के राष्ट्रपति काल में ये नीतियां ज्यादा आक्रामक रूप में सामने आई हैं।

परिवार परवरिश में महिला की भूमिका अनमोल

> "देश के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था 'पत्नी द्वारा घर के लिए दिया गया योगदान अमूल्य है और उसे धन के रूप में मापा नहीं जा सकता। पत्नी द्वारा अपने बच्चों और पति के प्रति सच्चे प्रेम और स्नेह के साथ तथा घरेलू मामलों के प्रबंधन में जो निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से नहीं की जा सकती।'

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में मोटर दुर्घटना में मृतक गृहिणी के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे को 58.22 लाख से बढ़ाकर 1.18 करोड़ कर दिया है। न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गृहिणी का काम अमूल्य है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को खुले बाजार में आउटसोर्स किया जाता, तो उन्हें काफी अच्छा वेतन मिलता।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि न्यायालय को गृहिणी के श्रम के अवमूल्यन को लेकर कठोर टिप्पणी करनी पड़ी हो। 27 अप्रैल, 2009 को 'नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नाबालिग दीपिका' के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 2000 के यूनिसेफ के उद्धरण को दिया। यूनिसेफ ने कहा था कि 'अवैतनिक देखभाल कार्य मानवीय अनुभव का आधार है'। देखभाल कार्य वह है जो एक महिला मां के रूप में करती है और निश्चित रूप से भारत में, मां की भूमिका की सामाजिक अवधारणा को देखते हुए, महिला स्वयं इस भूमिका को आर्थिक मूल्य देने वाली अंतिम व्यक्ति होगी। लेकिन जब हम किसी दुर्घटना में मां की मृत्यु के कारण बच्चे को हुए नुकसान का आकलन कर रहे होते हैं, तो हम देखभालकर्ता के कार्य को मौद्रिक मूल्य देना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि अंततः, घर ही वह मूलभूत इकाई है जिस पर हमारा सभ्य समाज टिका हुआ है।'

ठीक इसी तरह 2010 में 'अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड', मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था 'पत्नी द्वारा घर के लिए दिया गया योगदान अमूल्य है और उसे धन के रूप में मापा नहीं जा सकता। पत्नी द्वारा अपने बच्चों और पति के प्रति सच्चे प्रेम और स्नेह के साथ घरेलू मामलों के प्रबंधन में जो निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से नहीं की जा सकती।' न्यायालय ने यह भी कहा 'पत्नी/माता द्वारा परिवार—अर्थात् पति और बच्चों—को दी गई सेवाओं के एवज में किसी भी राशि का परिमाण निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करने के उद्देश्य से, गृहिणी/माता की सेवाओं का कुछ आर्थिक आकलन किया जाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में 'सेवाएं' शब्द को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और इसका निर्माण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि मृतका द्वारा एक माता के रूप में अपने बच्चों को तथा एक पत्नी के रूप में अपने पति को दी गयी व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान अब उपलब्ध नहीं रहा। आश्रित, मृतका द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क सेवाओं की हानि के बदले पर्याप्त प्रतिकर पाने के हकदार हैं। देय राशि इस आधार पर कम नहीं की जा सकती कि कोई निकट संबंधी, जैसे दादी, स्वेच्छा से परिवार को कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आ सकता/सकती है, जो पहले मृतका द्वारा दी जाती थीं।' न्यायालय के इस मामले में केम्प एंड केम्प द क्वांटम ऑफ़ डैमेज़ेज़ का उल्लेख किया गया था।

उल्लेखनीय है कि केम्प एंड केम्प द क्वांटम ऑफ़ डैमेज़ेज़ टॉर्ट लॉ (नुकसान की भरपाई का कानून) पर आधारित एक विधिक ग्रंथ है, जिसे विशेष रूप से मुआवज़े की गणना के लिए मानक संदर्भ माना जाता है। इसमें प्रतिपादित किया गया है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण केवल आय की प्रत्यक्ष हानि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उस वास्तविक, व्यावहारिक तथा संभावित क्षति का भी समुचित आकलन किया जाना चाहिए, जो मृतक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के अभाव में उसके आश्रितों को सहन करनी पड़ती है। यदि मृतक एक गृहिणी थी, तो यह कहना कि वह परिवार के लिए कोई आर्थिक योगदान नहीं देती थी, न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत, क्योंकि गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सेवाएं—जैसे भोजन तैयार करना, बच्चों का पालन-पोषण, घरेलू प्रबंधन, पारिवारिक सदस्यों की देखभाल तथा नैतिक और बौद्धिक मार्गदर्शन—स्वभावतः अत्यंत मूल्यवान होती हैं, भले ही उनके लिए कोई प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्राप्त न होता हो।

ग्रंथ यह स्पष्ट करता है कि ऐसी सेवाओं का मूल्यांकन बाज़ार में उपलब्ध समकक्ष सेवाओं की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति इन सेवाओं की भावनात्मक, नैतिक और निरंतर गुणवत्ता की पूर्ण भरपाई नहीं कर सकता। अतः न्यायालयों को गृहिणी की सेवाओं के मूल्यांकन में यथार्थवादी, व्यापक एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

वर्ष 1934 में, अमेरिकी अर्थशास्त्री मार्गरेट रीड ने एक अलग दृष्टिकोण सुझाते हुए तर्क दिया कि यदि गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक कार्यों के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है, तो ऐसे कार्यों को उत्पादन के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। दुनिया भर की अदालतें यह मानती हैं कि गृहिणियों के योगदान को नकारा जाता रहा है। इस संदर्भ में 'मेहमत बनाम पेरी (1977) 2 ऑल ईआर 529' में इंग्लैंड की अपीलीय अदालत की टिप्पणी गौरतलब है कि 'पत्नी द्वारा परिवार को दी जाने वाली सेवाएं केवल घरेलू कार्य तक सीमित नहीं हैं।' न्यायालय ने बच्चों के प्रति मातृत्व-देखभाल तथा पति के प्रति व्यक्तिगत ध्यान और संगति की हानि को स्वतंत्र क्षतिपूर्ति योग्य शीर्ष माना। यह निर्णय स्थापित करता है कि पत्नी/माता की निःशुल्क सेवाओं का वास्तविक आर्थिक मूल्य है और उसे साधारण घरेलू कर्मचारी की सेवाओं के समकक्ष नहीं आंका जा सकता। अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड', मामले में सर्वोच्च न्यायालय नेसेडॉ (सीईडीएडब्ल्यू) सम्मेलन की सामान्य सिफारिश संख्या 17 का उल्लेख किया था।

उक्त सामान्य सिफारिश महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों के मापन और मात्रा निर्धारण तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनकी मान्यता से संबंधित है। प्रासंगिक सिफारिशें 'महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों को मापने और उनका मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान और प्रयोगात्मक अध्ययनों को प्रोत्साहित और समर्थन करती है। उदाहरण के लिए, अपने राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में समय-उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करके और घरेलू और श्रम बाजार दोनों में गतिविधियों पर बिताए गए समय पर लिंग के आधार पर अलग-अलग आंकड़े एकत्र करके; महिलाओं की उन्नति के लिए रणनीतियों की तलाश करने, महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करने और उनका मात्रात्मक मूल्यांकन करने की बात करती है। साथ ही अनुच्छेद 18 अपारिश्रमिक घरेलू गतिविधियों को मापने और उनका मूल्यांकन करने के लिए किए गए अनुसंधान और प्रयोगात्मक अध्ययनों के साथ-साथ राष्ट्रीय खातों में महिलाओं की अपारिश्रमिक घरेलू गतिविधियों को शामिल करने में हुई प्रगति के बारे में जानकारी शामिल करने की वकालत करता है। भारत उक्त सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने 9 जुलाई, 1993 को सीईडी सम्मेलन की पुष्टि की। लेकिन तब भी उचित व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिससे महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों का मूल्यांकन हो सके।

प्रेरणा

परोपकार और त्याग से सजा महान जीवन

गोपबंधु दास भारतीय समाज के उन विरले व्यक्तित्वों में से थे, जिनके लिए मानवता कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सहज धड़कन थी। उन्हें 'उत्कल-मणि' कहा गया, पर यह उपाधि उनके बौद्धिक तेज या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि उनकी करुणा, संवेदना और त्याग के कारण उन्हें मिली। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा मानव वही है, जो दूसरों के दुख को देखकर केवल सहानुभूति ही नहीं जताता, बल्कि भीतर तक उसे महसूस करता है। उनके लिए सेवा कोई अवसर नहीं थी, जिसे समय देखकर किया जाए, बल्कि वह श्वास की तरह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी।

एक बार उनके पड़ोस के एक गांव में भयानक आग लग गई। कुछ ही घंटों में कई घर जलकर राख हो गए। जिन झोपड़ियों में जीवन की छोटी-छोटी खुशियां बसी थीं, वे देखते ही देखते लपटों में घिर गईं। लोग अपने बच्चों, बूढ़ों और पशुओं को लेकर इधर-उधर भाग रहे थे। किसी के पास सिर छुपाने की जगह नहीं थी, किसी के पास अन्न नहीं था। जैसे ही यह समाचार गोपबंधु दास तक पहुंचा, उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के अपने छात्रों और शिक्षकों को साथ लिया और तुरंत उस गांव की ओर चल पड़े। न उन्होंने अपनी सुविधा देखी, न मौसम, न थकान। उनके भीतर बस एक ही भावना थी—पीड़ितों के साथ खड़े होने की। आग बुझाने में वे स्वयं जुट गए। उन्होंने बाल्टी उठाई, मलबा हटाया, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और जिनकी आंखों में भय था, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उस दिन उन्होंने न केवल शारीरिक श्रम किया, बल्कि टूटे हुए मनों को भी संभालने की कोशिश की। जब आग शांत हुई और स्थिति कुछ सामान्य हुई, तब वे लौट आए। बाहर से देखने पर लगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, पर उनके मन के भीतर यह घटना समाप्त नहीं हुई थी।

दो दिन बाद की बात है। छात्रालय में सब अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। आधी रात के करीब अचानक तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जैसे धरती पर नहीं, बल्कि किसी के हृदय पर गिर रही हों। उसी सन्नाटे में कहीं से धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। यह आवाज इतनी करुण थी कि जिसने भी सुनी, उसका हृदय कांप उठा। छात्रालय में रहने वाले अधेड़ हरिहर दास की नींद टूट गई। उन्होंने ध्यान से सुना और उस दिशा में बढ़े, जहां से रोने की आवाज आ रही थी।

पांच-छह कमरों को पार करने के बाद वे उस कमरे के सामने पहुंचे, जहां गोपबंधु दास रहते थे। उन्होंने धीरे से किवाड़ खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो दृश्य असामान्य था। गोपबंधु दास बैठे हुए रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो भीतर का सारा दुख बाहर आ गया हो। हरिहर दास स्तब्ध रह गए। इतने वर्षों में उन्होंने कभी उन्हें इस तरह टूटते नहीं देखा था। इसी बीच अन्य छात्र भी जाग गए और धीरे-धीरे सब वहां इकट्ठा हो गए। सबके मन में एक ही प्रश्न था—आखिर दास जी क्यों रो रहे हैं?

कुछ क्षणों का गहरा मौन छा गया। फिर हरिहर दास ने साहस करके पूछा, "दास जी, आप क्यों रो रहे हैं?" यह प्रश्न सीधा था, पर उत्तर हृदय को झकझोर देने वाला। गोपबंधु दास ने भारी स्वर में कहा, "मैं यहां सुरक्षित छत के नीचे, सूखे बिस्तर पर लेटा हूं। बाहर आंधी और बारिश है। दो दिन पहले जिन लोगों के घर आग में जल गए थे, वे इस समय कहां होंगे? अपने बाल-बच्चों और पशुओं को लेकर वे किस खुले आकाश के नीचे बैठे होंगे? यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए।"

उनके शब्दों ने वहां खड़े सभी लोगों को मौन कर दिया। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक सुरक्षित व्यक्ति, जिसे स्वयं किसी अभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा, वह दूसरों की पीड़ा से इतना व्यथित हो सकता है। उस क्षण छात्रों को समझ में आया कि सच्ची करुणा क्या होती है। यह वह करुणा नहीं थी, जो मंचों पर भाषणों में दिखाई देती है, बल्कि वह करुणा थी, जो रात की नींद छीन लेती है।

गोपबंधु दास का दुख किसी व्यक्तिगत क्षति से नहीं जुड़ा था। उनका घर सुरक्षित था, उनका शरीर स्वस्थ था, फिर भी उनका हृदय अशांत था, क्योंकि कहीं कोई असुरक्षित था। यही मानवता का सर्वोच्च रूप है—दूसरों के लिए बेचैन होना। उस रात गोपबंधु दास ने बिना किसी उपदेश के छात्रों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि संवेदनशील बनना भी है।

अगली सुबह वे फिर उसी गांव की ओर जाने की तैयारी करने लगे। इस बार उनके साथ छात्रों का एक बड़ा समूह था। अब वे केवल देखने वाले नहीं थे, बल्कि सहभागी बन चुके थे। वे समझ चुके थे कि समाज में परिवर्तन केवल योजनाओं से नहीं आता, बल्कि संवेदनशील हृदयों से आता है। गोपबंधु दास की वह करुणा छात्रों के भीतर भी अंकुरित हो चुकी थी।

आज के समय में, जब हम अक्सर अपने आराम और सुविधा में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों के दुख हमें छू भी नहीं पाते, गोपबंधु दास का यह प्रसंग हमें आईना दिखाता है। वह हमें याद दिलाता है कि मानवता प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में प्रकट होता है। यदि किसी अनजान पीड़ित की चिंता हमें रात में जगा दे, यदि किसी बेघर की पीड़ा हमारी आंखों को नम कर दे, तभी हम सही अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य होते हैं। गोपबंधु दास की वह बरसाती रात आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए रो सकने में छिपी होती है।

आम बजट 2026-27 से होगा समावेशी विकास, विकसित बनेगा भारत

राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने अमृत काल में विकसित भारत के दृष्टिगत विगत एक दशक से जारी अनवरत समावेशी विकास के तहत एनडीए सहयोगियों को भरोसे में लेकर जिस प्रकार से आम बजट 2026-27 को प्रस्तुत किया, उसमें आरएसएस की जनोन्मुखी सोच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी दूरदर्शिता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक शिल्पकारिता का सटीक संदेश मिलता है। इससे विगत 12 वर्षों से जारी चतुर्दिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, और सियासी संसारमें मजबूत भारत का डंका बजेगा। भारत अब अमेरिका और चीन से प्रतियोगिता करेगा और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से अगले दशक तक उन्हें भी मात देगा। दुनियादारी के विशेषज्ञों की टिप्पणियों से भी इस बात की तस्दीक की जा सकती है।

आम बजट 2026-27 साफगोई पूर्वक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को रेखांकित करता है। यह केंद्रीय बजट भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। दरअसल, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाए रखने के लिए जो निर्णायक कदम उठाए हैं, उससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी। चूंकि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा करती है, इसलिए उसकी समग्र बेहतरी के लिए लाया हुआ यह युवा बजट हरेक दृष्टि जनकल्याणकारी है।

वर्तमान बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है, जिससे सबका साथ, सबका विकास जैसी लोकतांत्रिक जनभावना को जनविश्वास हासिल होता है और सरकार को मजबूती मिलती है। सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, कामगारों, उद्यमियों और बुजुर्गों के निजी व सार्वजनिक हितों का संबर्धन होता रहे। मौजूदा बजट हमारे लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रगति करता है, देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में काम करने वालों के उज्ज्वल भविष्य को मजबूत बनाता है, नए रोजगार और कौशल बढ़ाता है, जिससे निश्चय ही विकास की गति तेज होगी। इसलिए मैं इस बजट को विकसित भारत 2047 के स्वर्णिम भविष्य के लिए तैयार युवा बजट कहूंगा। क्योंकि यह वास्तव में एक ऐसा बजट है जो भारत की जरूरत और लक्ष्य को हासिल करने की नींव रखता है। जैसा कि हमारे दिग्गज नेताओं ने एक स्वर से कहा भी है कि यह आम बजट देश और इसकी जनता के अरमानों को पंख लगाता है, जिससे गरीब, युवा और बेरोजगार सबको आगे बढ़ने के सुनिश्चित साधन मिलते हैं। चूंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास और भरोसा करती है, इसलिए बजट का मुख्य उद्देश्य विकास और प्रगति दोनों है, क्योंकि इसमें देश और उसकी जनता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है।इसके सभी प्रावधान आम जनता के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए आम बजट 2026-27 विकास और प्रगति पर केंद्रित बजट है। जिससे देश के लोग खुश हैं। इस बजट की सियासी आलोचना के अलावा अन्य की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे मोदी है तो मुमकिन है, का भाव और मजबूत हुआ है। वाकई संसद में पेश केंद्रीय बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण जोशीला अगला कदम है, जो गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की जरूरत पूरी करता है और उनकी व्यापक भलाई सुनिश्चित करता है। यह युवा बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कार्यकुशल सियासी व प्रशासनिक टीम पर लोगों के अटूट भरोसे को दिखाता है। यह इस बजट के हर पहलू में साफ दिखता है।

सच कहूं तो भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई चौथी अर्थव्यवस्था है, जिसे शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के निमित्त यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में तेजी आएगी। इस प्रकार यह बजट स्पष्ट रूप से भविष्य में भारत को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाता है। जब महज 12 वर्षों के भाजपा और राजग शासनकाल में भारत, अमेरिका और चीन को रणनीतिक कूटनीतिक स्वायत्तता जैसी टक्कर देने की स्थिति में पहुंच चुका है तो अगले 10 वर्षों और खासकर विकसित भारत 2047 तक भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत क्या होगी, समझना मुश्किल नहीं है।

अभियान

जहां आस्था आज भी महादेव की शरण में सांस लेती है, शिवखोड़ी गुफा की रहस्यमयी और दिव्य गाथा

भारत की आध्यात्मिक परंपरा केवल शास्त्रों और मंदिरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह प्रकृति के कण-कण में समाई हुई है। पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और श्मशान—सब शिव तत्व के साक्षी रहे हैं। ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी स्थलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जम्मू-कश्मीर की शिवखोड़ी गुफा, जिसे लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि स्वयं भगवान शिव ने यहां भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शिव आज भी सपरिवार कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय उनके साथ विराजमान हैं। किंतु जम्मू क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आस्था इस धारणा से कहीं आगे जाती है। उनके अनुसार महादेव केवल कैलाश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे शिवखोड़ी गुफा में आज भी अपने दिव्य स्वरूप में विद्यमान हैं। जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर दूर ऊधमपुर जिले के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित यह गुफा केवल एक पर्यटन या धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, भय, चमत्कार और रहस्य का अद्भुत संगम है। शिवखोड़ी गुफा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि धरती के गर्भ में बनी एक लंबी और संकरी सुरंग हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा का दूसरा सिरा सीधे बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में जाकर खुलता है। यद्यपि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पूरे मार्ग को पार नहीं कर सका और न ही इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है, फिर भी श्रद्धालुओं के विश्वास में यह कथा अडिग बनी हुई है। यही कारण है कि शिवखोड़ी गुफा को अमरनाथ के समान ही चमत्कारी और दिव्य माना जाता है।

इस गुफा से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और भय मिश्रित मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति गुफा के भीतर गहराई तक प्रवेश करता है, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। इसी विश्वास के कारण कोई भी श्रद्धालु गुफा के अंतिम छोर तक जाने का साहस नहीं करता। भक्त गुफा के प्रवेश द्वार और आरंभिक भाग तक ही दर्शन करते हैं और वहीं भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन समय में महान साधु-संत और तपस्वी इसी गुफा के मार्ग से बाबा अमरनाथ की यात्रा किया करते थे। उस काल में साधना और तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे इस रहस्यमयी मार्ग को पार करने में सक्षम थे, किंतु कलियुग में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ, जो इस गुफा में प्रवेश कर उसके रहस्य को भेद सके।

शिवखोड़ी गुफा की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्वयंभू शिवलिंग है। यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि चट्टानों के प्राकृतिक आकार से स्वतः प्रकट हुआ है। जिस प्रकार बाबा अमरनाथ की गुफा में बर्फ से शिवलिंग बनता है, उसी प्रकार यहां पत्थर की संरचना ने शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लिया है। भक्त इसे भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करते हैं। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी नंदी की आकृति, माता पार्वती के स्वरूप जैसी चट्टानें और छत पर उभरी हुई सर्पाकार आकृतियां इस विश्वास को और भी प्रगाढ़ कर देती हैं कि यह स्थान केवल प्रकृति की देन नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति की रचना है।

लगभग 200 मीटर लंबी यह गुफा कहीं-कहीं मात्र 1 मीटर चौड़ी है, जबकि इसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक पहुंच जाती है। भीतर प्रवेश करते ही वातावरण में एक अलौकिक शांति और ठंडक का अनुभव होता है। हल्की रोशनी में जब चट्टानों पर बनी आकृतियां दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पत्थर भी कथा कह रहे हों। यहां का हर कण शिव तत्व से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और मन अनायास ही ध्यान और भक्ति में डूबने लगता है। समय जैसे यहां आकर ठहर जाता है और बाहरी संसार का कोलाहल पीछे छूट जाता है।

शिवखोड़ी गुफा की दिव्यता का सबसे बड़ा आधार इससे जुड़ी पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भस्मासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दे दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह तत्काल भस्म हो जाएगा। शिवजी उस समय असुर की कुटिल मंशा से अनजान थे। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को यह अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ, उसका अहंकार जाग उठा और उसने स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया।

भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ा। यह कोई साधारण पलायन नहीं था, बल्कि महादेव की लीला थी, जिसमें उन्होंने असुर के अहंकार को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त किया। कहा जाता है कि इसी क्रम में भगवान शिव एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और वहां एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए। यही गुफा आगे चलकर शिवखोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भस्मासुर लंबे समय तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन जब वह शिवजी को खोज नहीं पाया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य इतना मोहक था कि भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। मोहिनी के साथ नृत्य करते हुए वह अपने वरदान को भूल गया। नृत्य की मुद्राओं की नकल करते हुए उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और उसी क्षण वह अपने ही वरदान के कारण भस्म हो गया। इस प्रकार शिवजी की रक्षा हुई और शिवखोड़ी गुफा उनकी लीला और संरक्षण का प्रतीक बन गई। तभी से यह गुफा भगवान शिव की शरणस्थली और उनके चमत्कारों की साक्षी मानी जाती है। आज भी शिवखोड़ी गुफा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सावन का महीना और महाशिवरात्रि का पर्व यहां विशेष महत्व रखते हैं। इन अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई रोग से मुक्ति की कामना लेकर आता है, कोई संतान सुख की प्रार्थना करता है, तो कोई जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने की आस लेकर यहां शीश झुकाता है। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और निष्कलंक भाव से शिवखोड़ी गुफा में मन्नत मांगता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं।

शिवखोड़ी गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पौराणिक चेतना और आस्था की जीवंत धरोहर है। यह स्थान यह सिखाता है कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे वहां निवास करते हैं जहां श्रद्धा उन्हें पुकारती है। विज्ञान इन कथाओं को तर्क की दृष्टि से देख सकता है, किंतु आस्था का संसार तर्क से नहीं, विश्वास से संचालित होता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी शिवखोड़ी गुफा उतनी ही रहस्यमयी, पवित्र और श्रद्धा से परिपूर्ण बनी हुई है। यहां आकर व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि यह अनुभव करता है कि महादेव आज भी इसी धरती पर कहीं न कहीं अपनी दिव्य लीला रच रहे हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान",जन जागरूकता अभियान में एम्बुलेंस 108 टीम की सक्रिय सहभागिता

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा डिजिटल रेलवे सेवाओं के अधिकाधिक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" जन जागरूकता अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। यह अभियान प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरूण जैन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 04 फरवरी 2026 (बुधवार) को भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर एक प्रभावी जन जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एम्बुलेंस 108 के हेड श्री कपिल सोलंकी एवं उनकी टीम की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान भावनगर मंडल की कल्चरल टीम एवं स्काउट एवं गाइड की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों एवं स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर एम्बुलेंस 108 की टीम ने एंबुलेंस में उपलब्ध जीवनरक्षक उपकरणों की विस्तृत जानकारी दी तथा आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में बिना किसी हिचक के 108 सेवा का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। टीम द्वारा समय पर एम्बुलेंस बुलाने की प्रक्रिया, दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं प्राथमिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गईं।

कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को रेलवन ऐप (RailOne App) की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यात्रियों को ऐप के प्रमुख लाभों जैसे आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी तथा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया एवं डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल सेवाओं को अपनाने तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी एवं कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की कि वे सदैव उचित टिकट लेकर यात्रा करें तथा इस संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियानों से यात्रियों में रेलवे नियमों, नागरिक कर्तव्यों, ईमानदार यात्रा एवं सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर मान. मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर से आई भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया केवल एक औपचारिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर पेश करती है जो आज विश्व मंच पर आत्मविश्वास, सामर्थ्य और स्पष्ट दृष्टि के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह इस समझौते को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व से जोड़ते हुए "नए भारत की शक्ति" का परिचय बताया है, उससे स्पष्ट होता है कि यह डील सिर्फ दो देशों के बीच व्यापारिक आंकड़ों या टैरिफ दरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक रणनीति, कूटनीतिक परिपक्वता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह रेखांकित किया कि भारत और अमेरिका के बीच हुई यह ट्रेड डील केवल उद्योगों के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के हित में नए अवसरों के सृजन का माध्यम भी है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और संरक्षणवाद जैसी चुनौतियाँ सामने हैं, ऐसे समय में दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक साथ आगे बढ़ना अपने-आप में एक सकारात्मक संकेत है। यह साझेदारी यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर वैश्विक कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री के वक्तव्य में यह भावना भी स्पष्ट रूप से झलकती है कि यह ट्रेड डील भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते केवल रणनीतिक या रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, स्टार्टअप और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी गहराई से जुड़े हैं। इस समझौते से इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को एक नया आयाम मिलेगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच भरोसे का स्तर और मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" के विजन को मुख्यमंत्री ने इस डील से मिलने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में रेखांकित किया। अमेरिकी टैरिफ का घटकर 18 प्रतिशत होना कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई, निर्यातक और उससे जुड़े लाखों कामगारों के लिए यह एक नई उम्मीद लेकर आएगा। जब निर्यात बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा, तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस तरह यह समझौता आर्थिक विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस व्यापार समझौते से उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजारों के नए द्वार खुलेंगे। आज का भारत केवल कच्चा माल या पारंपरिक उत्पाद निर्यात करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नवाचार, तकनीक और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे बड़े और परिष्कृत बाजार तक आसान पहुंच भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल पूंजी निवेश बढ़ेगा, बल्कि तकनीकी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

गुजरात के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुजरात पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में गुजरात की अग्रणी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। भारत-अमेरिका के इस ऐतिहासिक समझौते से इन सभी क्षेत्रों के उत्पादों के निर्यात को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सीधा लाभ गुजरात के उद्योगों, एमएसएमई इकाइयों और व्यापारिक समुदाय को मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि इस समझौते से भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, भारत का एक मजबूत आर्थिक भागीदार के रूप में उभरना न केवल देश के लिए, बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। अमेरिका के साथ इस तरह का व्यापारिक सहयोग भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देगा। श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और नागरिक-केंद्रित कूटनीति की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी दृष्टिकोण के कारण भारत-अमेरिका संबंध केवल सरकारी या कूटनीतिक स्तर तक सीमित न रहकर आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक शांति और समृद्धि को गति देने में ऐसे समझौतों की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि आर्थिक सहयोग अक्सर राजनीतिक स्थिरता और आपसी विश्वास को भी मजबूत करता है। अपने वक्तव्य के अंत में मुख्यमंत्री ने गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बधाई दी। यह बधाई केवल एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि उस भरोसे की अभिव्यक्ति है जो देश और राज्य की जनता को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील आने वाले वर्षों में किस तरह भारतीय उद्योग, रोजगार, नवाचार और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, यह समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह समझौता नए भारत की उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें देश आत्मनिर्भरता के साथ-साथ विश्व के लिए भी एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार बनकर उभर रहा है।

हापा - नाहरलगून स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित

(जीएनएस)। रतलाम। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर परिचालित गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल की सेवाओं का विस्तार किया गया है।

गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल को पहले 25 फरवरी 2026 तक तथा गाड़ी संख्या 09526 नाहरलगून - हापा स्पेशल को 28 फरवरी 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब बढ़ाते हुए दोनों दिशाओं में अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल हापा से 04 मार्च 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक एवं इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09526 नाहरलगून - हापा स्पेशल नाहरलगून से 07 मार्च 2026 से 02 जनवरी 2027 तक अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कोच एवं ट्रेन संचालन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस समय में आंशिक बदलाव

(जीएनएस)। रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से गुजरने वाली अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस का अहमदाबाद एवं दरभंगा से प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। विवरण इस प्रकार है –

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 19165 अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस –06 फरवरी, 2026 से अहमदाबाद स्टेशन से 19.15 बजे के स्थान पर 19.25 बजे प्रस्थान करेगी। इसीप्रकार गाड़ी संख्या 19166 दरभंगा - अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस –01 अप्रैल 2026 से यह ट्रेन दरभंगा स्टेशन से 04.30 बजे के स्थान पर 04.20 बजे प्रस्थान करेगी। अन्य स्टेशनों पर इसके आगमन/प्रस्थान समय में कोई बदलाव किया गया।

यात्रीगण कृपया कोच एवं ट्रेन संचालन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में श्री जतिन ठक्कर को शपथ दिलाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर में गुजरात विद्युत नियामक आयोग (जीईआरसी-जर्क) के सदस्य के रुप में नियुक्त किए गए श्री जतिन ठक्कर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर जर्क के अध्यक्ष श्री पंकज जोषी, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री राजेंद्र सरीन और विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों सहित वरिष्ठ सचिव और अधिकारी मौजूद रहे।

कोयंबत्तूर – जयपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन : विस्तारित

(जीएनएस)। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कोयंबत्तूर – जयपुर के फेरों को पुनः विस्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 06181 कोयंबत्तूर–जयपुर स्पेशल दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कोयंबत्तूर से प्रति गुरुवार को प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 06182 – जयपुर –कोयंबत्तूर स्पेशल दिनांक 22 फरवरी 2026 तक जयपुर से प्रति रविवार को प्रस्थान करेगी। यात्रीगण ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

उत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण इंदौर–शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम। उत्तर रेलवे में निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी । ब्लॉक कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर से संचालित होने वाली इंदौर–शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर-इंदौर एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 मई 2026 तक इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22941 इंदौर - शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा जालंधर कैंट से शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर तक निरस्त रहेगी। इसी प्रकार 27 मई 2026 तक शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22942 शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर - इंदौर एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा शहीद कैप्टन तुषार महाजन इंदौर उधमपुर से जालंधर कैंट तक निरस्त रहेगी। ट्रेनों के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर–ओखा एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूलित कोच की सुविधा 31 मई 2026 तक विस्तारित

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन (19209/19210) में अस्थायी रूप से प्रदान की जा रही वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (थर्ड एसी) कोच की सुविधा को 31 मई 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस में एक थर्ड एसी कोच भावनगर टर्मिनस स्टेशन से दिनांक 05 फरवरी 2026 से 31 मई 2026 तक लगाया जाएगा। वहीं ओखा स्टेशन से यह कोच दिनांक 06 फरवरी 2026 से 01 जून 2026 तक संचालित रहेगा।

उक्त ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारिणी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

एलसी संख्या 95 पर आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु अस्थायी यातायात परिवर्तन

(जीएनएस)। भावनगर मंडल के अंतर्गत साबरमती–बोटाद रेल खंड में स्थित लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 95 पर आवश्यक बड़े मरम्मत एवं सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाने हैं। इस कार्य के कारण सड़क यातायात को दिनांक 05 फरवरी 2026 को रात्रि 20.00 बजे से 06 फरवरी 2026 को सायं 17.00 बजे तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान यात्रियों एवं वाहन चालकों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था

बगोदरा से धंधुका की ओर जाने वाले वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग:

बगोदरा – अरणेज – जवारज – गुंदी से फेदरा होकर धंधुका।

धंधुका से बगोदरा की ओर जाने वाले वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग:

धंधुका से फेदरा और फेदरा से गुंदी गाँव होकर अरणेज और बगोदरा।

पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल आम जनता से अपील करता है कि वे असुविधा से बचने हेतु निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सहयोग प्रदान करें।

यह कार्य यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की दीर्घकालिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसके लिए जनता से सहयोग की अपेक्षा है।

गांधीग्राम–भावनगर ट्रेन में छूटा यात्री का बैग वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की तत्परता से सुरक्षित मिला

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के कर्मचारी अपने सम्मानित यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 04 फरवरी, 2026 (बुधवार) को एक यात्री ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम–भावनगर स्पेशल से धोला स्टेशन तक यात्रा कर रहा था। धोला स्टेशन पर उतरने के पश्चात तथा ट्रेन के प्रस्थान के बाद यात्री को यह ज्ञात हुआ कि उसका एक सुटकेस ट्रेन में ही छूट गया है। उक्त सुटकेस में लगभग 21,000/- मूल्य का एक मोबाइल फोन, 1,00,000/- मूल्य की सोने की बुटी,

25,000/- नकद (Cash), नए कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामान रखा हुआ था।

यह सुटकेस ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक–भावनगर श्री एस. डी. गोहिल को लावारिस अवस्था में मिला। इधर, यात्री तुरंत सड़क मार्ग से भावनगर टर्मिनस पहुंचा और स्टेशन पर अपने छूटे हुए सुटकेस के संबंध में जानकारी दी। आवश्यक पूछताछ एवं पहचान सत्यापन के उपरांत सुटकेस को यात्री को सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया।

अपना सामान सही-सलामत प्राप्त होने पर यात्री ने रेल प्रशासन एवं सभी संबंधित कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए संबंधित कर्मचारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया तथा कहा कि भावनगर मंडल अपने यात्रियों की सुरक्षा, सेवा और विश्वास बनाए रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

श्री सहर्ष बाजपाई ने पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया

(जीएनएस)। भारतीय रेल कार्मिक सेवा (IRPS) के 1999 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री सहर्ष बाजपाई ने मंगलवार, 03 फ़रवरी 2026 को पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री बाजपाई भारतीय रेल में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कार्मिक संबंधी पदों पर कार्य कर चुके हैं। आपने उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे, मध्य रेल तथा महाराष्ट्र मेट्रो में प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन किया है। आपके द्वारा संभाले गए उल्लेखनीय पदों में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, पुणे; अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मध्य रेल; उप मुख्य कार्मिक अधिकारी; अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, पुणे; महा मेट्रो में महाप्रबंधक (मानव संसाधन); तथा मध्य रेल में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी शामिल हैं। श्री सहर्ष बाजपाई ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर (MPA) की डिग्री प्राप्त की है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन तथा नीति निर्माण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। अपने करियर के दौरान आप मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) को सुदृढ़ करने, कार्मिक प्रशासन में सुधार लाने तथा कर्मचारी-केंद्रित शासन पद्धतियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। फील्ड इकाइयों एवं मुख्यालय स्तर पर आपके व्यापक अनुभव ने आपको कार्मिक प्रबंधन के प्रति संतुलित एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया है। श्री बाजपाई ने INSEAD, सिंगापुर; ICLIF, मलेशिया; KOTI, दक्षिण कोरिया; तथा SWJTU, चीन जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए एकतानगर स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा एकतानगर स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों के समय मे परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का परिवर्तित समय का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09410 एकतानगर-अहमदाबाद स्टीम हेरिटेज स्पेशल (द्वि-साप्ताहिक) 14.02.2026 से एकतानगर स्टेशन से 20:20 बजे की बजाय अब 20:30 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 20950 एकतानगर - अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस 09.02.2026 से एकतानगर स्टेशन से 20:55 बजे की बजाय अब 20:50 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन नं 69206 एकतानगर - प्रतापनगर मेमू के संचालन समय में जो 10.02.2026 से परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन का एकतानगर स्टेशन पर 22.35 बजे के बजाय 21.05 बजे रवाना होगी। चांदोद स्टेशन पर 22.59/23.00 बजे के बजाय 22.14/22.15 बजे पहुंचेगी/रवाना होगी। डभोई स्टेशन पर 23.18/23.20 बजे के बजाय 22.33/22.35 बजे पहुंचेगी/रवाना होगी। प्रतापनगर स्टेशन पर 00.05 बजे के बजाय 23.15 बजे पहुंचेगी।

यात्री इस ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद मण्डल ने अप्रैल 2025 से जनवरी, 2026 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया ₹25.72 करोड़ से अधिक का जुर्माना

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों के माध्यम से 25.72 करोड़ से अधिक का जुर्माना प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल अपने यात्रियों की सुविधाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है और वैध यात्रियों की सुरक्षित एवं सुखद यात्रा सुनिश्चित करने हेतु अनेक सशक्त कदम उठा रहा है।

अनाधिकृत यात्रा की रोकथाम के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी एवं अन्य वाणिज्य अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन टिकट जांच कार्य की समीक्षा की गई तथा उनके मार्गदर्शन में विशेष टिकट जांच अभियान संचालित किए गए। वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में

कार्यरत अत्यंत प्रेरित टिकट चेकिंग टीम द्वारा अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान अनेक अभियान चलाए गए, जिनके परिणामस्वरूप 25.72 करोड़ की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 54% अधिक है। केवल जनवरी 2026 माह में ही बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं, 32,330 प्रकरणों की पहचान कर 2.48 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो निर्धारित लक्ष्य से 18% अधिक है।

दिनांक 04.02.2026 को मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री जयेश मकवाना के नेतृत्व में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत 14702 अमरापुर अरावली एक्सप्रेस, 79434 साबरमती–पाटन डेमू, 79432 साबरमती–महेसाणा डेमू, 79436 पाटन–साबरमती डेमू तथा 12547 आगरा कैंट–साबरमती एक्सप्रेस में सघन जांच की गई। इस अभियान में 10 टिकट जांच स्टाफ एवं 4 आरपीएफ स्टाफ की उपस्थिति रही। अभियान के दौरान बिना टिकट के 120, उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले 19, बिना बुक सामान का 1 तथा गंदगी फैलाने/थूकने के 4 प्रकरण सहित कुल 144 प्रकरण पकड़े गए, जिनसे 47,010 की वसूली की गई। यह अभियान साबरमती–महेसाणा एवं पाटन–साबरमती रेलखंडों में संचालित किया गया।

इस प्रकार के परिणाम अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल अपने यात्रियों से विनम्र अनुरोध करता है कि वे उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, जिससे उनकी यात्रा सुगम, सुरक्षित एवं आनंददायक हो।

कोहरे, ठंड और बदलते मिज़ाज के बीच उत्तर भारत का मौसम, पहाड़ों से मैदान तक असर

(जीएनएस)। उत्तर भारत इन दिनों मौसम के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ठंड, कोहरा, हल्की धूप और बदलते वायुमंडलीय दबाव ने आम जनजीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर मैदानों तक साफ महसूस किया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं साफ आसमान के बावजूद सर्द हवाएं परेशान कर रही हैं, तो कहीं घना कोहरा दृश्यता घटा रहा है और कहीं बारिश-ओलावृष्टि की आशंका किसानों की चिंता बढ़ा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक बारिश या घने कोहरे को लेकर कोई औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई है। इसके बावजूद ठंड का अहसास कम नहीं हुआ है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं राजधानी की ओर आ रही हैं, जिससे दिन के समय भी हवा में ठंडक बनी हुई है। सुबह और रात के समय तापमान गिरने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है, जो फरवरी के लिहाज से सामान्य से थोड़ा कम है।

हालांकि मौसम साफ होने के बावजूद दिल्ली की एक बड़ी परेशानी अभी भी जस की तस बनी हुई है और वह है वायु प्रदूषण। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर श्रेणी में आता है। आनंद विहार, अशोक विहार, द्वारका सेक्टर-8 और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में हवा बेहद खराब दर्ज की गई है। सुबह के समय हल्का धुंधनुमा माहौल और प्रदूषित हवा आंखों में जलन और सांस की दिक्कतें बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी और स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिससे स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हो पा रहा।

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिज़ाज दिल्ली से कुछ अलग नजर आ रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में कोहरे का असर ज्यादा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 10 से अधिक जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। दिन में धूप निकलने की संभावना जरूर है, लेकिन शीतलहर के चलते ठंड का असर बरकरार रहेगा। फिलहाल राज्य में बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन बदलते मौसम पैटर्न को देखते हुए किसान और ग्रामीण इलाकों के लोग सतर्क नजर आ रहे हैं।

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आने वाले दिनों में और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो अगले करीब चार दिनों तक प्रभावी रह सकता है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 6 फरवरी को कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हो सकती है, जबकि 9 और 10 फरवरी को एक बार फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम करवट ले सकता है। बर्फबारी से जहां पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह परेशानी भी खड़ी कर सकती है। सड़कों पर फिसलन, यातायात में बाधा और तापमान में तेज गिरावट आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है।

उत्तराखंड में फिलहाल ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं मानी जा रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। खासकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

मैदानी और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। यह स्थिति किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि इस समय कई फसलों की कटाई या अंतिम चरण चल रहा है। ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। वहीं शहरों में अचानक बारिश से तापमान में गिरावट और यातायात व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

मध्य प्रदेश में बीते दिनों बारिश और ओलावृष्टि के कारण मौसम पहले से ही सर्द बना हुआ है। कई जिलों में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी को एक बार फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इससे जहां तापमान में और गिरावट आएगी, वहीं किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। बदलते मौसम ने ग्रामीण इलाकों में रोजमर्रा की गतिविधियों को भी प्रभावित किया है।

कुल मिलाकर उत्तर भारत का मौसम इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। सर्दी की विदाई अभी दूर नजर आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय होकर मौसम को अस्थिर बना रहे हैं। शहरों में जहां प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार है, वहीं गांवों और पहाड़ी इलाकों में कोहरा, बर्फबारी और बारिश जनजीवन को चुनौती दे रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी के पहले पखवाड़े तक इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बदलते हालात के अनुसार अपनी दिनचर्या और यात्राओं की योजना बनाएं।

ख़ौफ, अंधेरा और एक पल की घबराहट, जंगली जानवर से बचने की कोशिश में मौत बन गया हाई-वोल्टेज खंभा

(जीएनएस)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लच्छीवाला इलाके में सोमवार शाम जो हुआ, उसने इंसानी डर, जंगल की नजदीकी और आधुनिक ढांचे की खतरनाक मौजूदगी—तीनों के टकराव को एक साथ उजागर कर दिया। यह हादसा सिर्फ एक युवक की दर्दनाक मौत नहीं है, बल्कि उस खामोश खतरे की कहानी भी है, जो जंगल से सटे इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी के साथ चलता रहता है। दून-हरिद्वार रेलवे ट्रैक के पास जीरो प्वाइंट क्षेत्र में एक युवक जंगली जानवर से बचने के प्रयास में ऐसा कदम उठा बैठा, जिसने उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया।

शाम का वक्त था, आसपास घना जंगल, हल्का अंधेरा और सन्नाटा। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल का यह युवक रेलवे ट्रैक के किनारे मौजूद था, तभी अचानक उसका सामना किसी जंगली जानवर से हो गया। प्रत्यक्षदर्शी तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन घटनास्थल और परिस्थितियों को देखकर पुलिस भी यही मान रही है कि युवक बुरी तरह घबरा गया था। जान बचाने की हड़बड़ी में उसने इधर-उधर भागने के बजाय पास ही लगे रेलवे के इलेक्ट्रिक पोल को सहारा समझ लिया। वह नहीं जानता था कि यह खंभा उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा साबित होगा।

डर के मारे युवक तेजी से हाई-वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ने लगा। जैसे-जैसे वह ऊपर बढ़ता गया, वैसे-वैसे उसकी जिंदगी के चंद आखिरी पल सिमटते चले गए। ऊपर पहुंचते ही वह ओवरहेड इक्विपमेंट यानी रेलवे की हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया। करंट इतना जबरदस्त था कि युवक को संभलने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के लिए भी दृश्य विचलित करने वाला था।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और हर्रावाला चौकी प्रभारी रघुवीर कपरूवाण टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े हाई-वोल्टेज पोल पर झुलसा हुआ शव देखकर हर कोई सन्न रह गया। युवक का शरीर इस कदर जल चुका था कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने विद्युत खंभे, आसपास की जमीन और ट्रैक क्षेत्र से साक्ष्य जुटाए। यह समझने की कोशिश की गई कि युवक किस दिशा से आया, कहां से चढ़ा और किस तरह करंट की चपेट में आया।

शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या धक्का दिए जाने के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस का मानना है कि यह पूरी तरह हादसा है, जो घबराहट और हालात की गलत समझ का नतीजा बना। मृतक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान तुरंत हो सके। शव के अत्यधिक झुलस जाने के कारण चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और आसपास के थानों व गांवों में युवक की फोटो और जानकारी साझा की गई, ताकि उसके परिजनों तक खबर पहुंचाई जा सके।

लच्छीवाला क्षेत्र लंबे समय से जंगली जानवरों की आवाजाही को लेकर चर्चा में रहा है। यह इलाका घने जंगल से सटा हुआ है, जहां हाथी, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवर अक्सर दिखाई देते हैं। शाम ढलते ही यहां डर का माहौल बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जंगली जानवर सड़क और रेलवे ट्रैक के आसपास आ जाते हैं, जिससे राहगीरों और मजदूरों में दहशत फैल जाती है। ऐसे में लोग घबराकर गलत फैसले ले बैठते हैं, जैसा इस युवक के साथ हुआ।

यह हादसा एक बार फिर जंगल से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता पर सवाल खड़े करता है। रेलवे के हाई-वोल्टेज खंभे आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता। डर की स्थिति में इंसान वही करता है, जो उसे उस पल सबसे सुरक्षित लगता है। इस युवक को भी शायद लगा होगा कि ऊंचाई पर चढ़कर वह जंगली जानवर से बच जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऊपर मौत उसका इंतजार कर रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में चेतावनी बोर्ड और रोशनी की व्यवस्था नाकाफी है।

किसानों की पीठ में छुरा या विकास का नाम पर समझौता? अमेरिका से संभावित डील पर आम आदमी पार्टी का तीखा हमला

(जीएनएस)। चंडीगढ़ से उठी आम आदमी पार्टी की आवाज़ ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के साथ संभावित व्यापारिक समझौते को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी ने जिस आक्रामक तेवर में सवाल खड़े किए हैं, उसने देश की राजनीति के साथ-साथ कृषि भविष्य को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। पार्टी का आरोप है कि यह कोई सामान्य व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के किसानों को बर्बाद करने और देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की साजिश है, जिसे चुपचाप और बंद दरवाजों के पीछे अंजाम देने की तैयारी की जा रही है।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि जब मामला देश के भविष्य और 80 करोड़ से अधिक लोगों की रोज़ी-रोटी से जुड़ा हुआ है, तो फिर इस समझौते की शर्तें संसद में क्यों नहीं रखी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन-सा दबाव है, जिसके चलते सरकार इस डील को देश से छिपा रही है। धालीवाल ने तीखे लहजे में कहा कि अगर यह सौदा किसानों और आम जनता के हित में है, तो इसे सार्वजनिक करने से सरकार क्यों डर रही है।

आप नेता ने इस मुद्दे को सिर्फ व्यापार तक सीमित न रखते हुए इसे देश की संप्रभुता और नीति निर्धारण से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिकी नेता सोशल मीडिया पर भारत की नीतियों को लेकर बयान दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री चुप हैं। धालीवाल ने पूछा कि भारत के लोगों के लिए ट्रंप आखिर कौन हैं। वह प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हो सकते हैं, लेकिन क्या दोस्ती के नाम पर देश के किसानों और उपभोक्ताओं के हितों से समझौता किया जा सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे ऐसी शर्तें तय हो चुकी हैं, जिन्हें सामने लाने पर देशभर में विरोध की आग भड़क उठे।

आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस सौदे के तहत भाजपा सरकार अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के दरवाज़े लगभग ज़ीरो टैक्स पर खोलने जा रही है। धालीवाल का कहना था कि अगर अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कपास, डेयरी उत्पाद, मछली और मीट सस्ते दामों पर भारतीय बाज़ार में उतरते हैं, तो देश के छोटे और मध्यम किसान कैसे टिक पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सस्ते आयातित उत्पादों की बाढ़ स्थानीय मंडियों को तबाह कर देगी और किसान अपनी ही ज़मीन पर पराए बनकर रह जाएंगे।

धालीवाल ने इसे सीधे-सीधे व्यापार नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण करार दिया। उनका कहना था कि यह भाजपा की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें कृषि क्षेत्र को कमजोर कर बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही महंगाई, बढ़ती लागत, कर्ज़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में अगर बाज़ार को विदेशी उत्पादों के लिए खोल दिया गया, तो उसका बचा-खुचा सहारा भी छिन जाएगा। यह सिर्फ आर्थिक हमला नहीं, बल्कि सामाजिक और ग्रामीण ढांचे पर भी गहरा प्रहार होगा।

आप प्रवक्ता ने अमेरिकी कृषि उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और जीएम फसलों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कृषि उत्पादन के मानक भारत से अलग हैं और वहां ऐसे रसायनों का इस्तेमाल आम है, जिन्हें भारत में या तो प्रतिबंधित किया गया है या जिन पर सख्त नियंत्रण है। ऐसे उत्पाद अगर भारतीय बाज़ार में आए, तो इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा मंडराएगा। धालीवाल ने सवाल किया कि क्या सरकार सिर्फ सस्ते दामों के लालच में लोगों की सेहत से समझौता करने को तैयार है।

तेल और ऊर्जा नीति को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने इस संभावित सौदे को खतरनाक बताया। धालीवाल ने आशंका जताई कि इस करार के तहत भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने पर दबाव बनाया जा सकता है और उसे अमेरिका से महंगा तेल आयात करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तेल महंगा हुआ, तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट, खेती, उद्योग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ महंगी हो जाएगी।

सोना-चांदी में तेजी जारी: सोना वायदा में 4932 रुपये और चांदी वायदा में 15784 रुपये का अधिक ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 133808.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 42166.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 91639.43 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 40400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3548.05 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 35850.83 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 158420 रुपये के भाव पर खूलकर, 160755 रुपये के दिन के उच्च और 156553 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153809 रुपये के पिछले बंद के सामने 4932 रुपये या 3.21 फीसदी की मजबूती के साथ 158741 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 3842 रुपये या 3.03 फीसदी बढ़कर 130682 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 510 रुपये या 3.23 फीसदी बढ़कर 16305 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मार्च वायदा 152849 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158664 रुपये और नीचे में 152849 रुपये पर पहुंचकर, 4863 रुपये या 3.2 फीसदी बढ़कर 156725 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 157270 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 163000 रुपये और नीचे में 152168 रुपये पर पहुंचकर, 155897 रुपये के पिछले बंद के सामने 5418 रुपये या 3.48 फीसदी बढ़कर 161315 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 278015 रुपये के भाव पर खूलकर, 286306 रुपये के दिन के उच्च और 275044 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268015 रुपये के पिछले बंद के सामने 15784 रुपये या 5.89 फीसदी की बढ़त के साथ 283799 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 15298 रुपये या 5.54 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 291596 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 15340 रुपये या 5.55 फीसदी की तेजी के संग 291763 रुपये प्रति किलो हुआ।

क्रूड ऑयल वायदा में 39 रुपये की वृद्धि: कमोडिटी वायदाओं में 42166.14 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 91639.43 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 35850.83 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40400 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 4205.44 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 25 पैसे या 0.02 फीसदी टूटकर 1282.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.6 रुपये या 0.49 फीसदी की बढ़त के साथ 325.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 65 पैसे या 0.21 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 315.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी घटकर 191.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1992.01 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5764 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5796 रुपये और नीचे में 5695 रुपये पर पहुंचकर, 39 रुपये या 0.68 फीसदी बढ़कर 5748 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 41 रुपये या 0.72 फीसदी की मजबूती के साथ 5751 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 301.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 305.6 रुपये के दिन के उच्च और 295.6 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 301.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.3 रुपये या 0.76 फीसदी की बढ़त के साथ 303.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 2.2 रुपये या 0.73 फीसदी बढ़कर 304 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 987 रुपये पर खूलकर, बिना बदलाव के 980.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20975.34 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 14875.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3758.58 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 158.46 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 26.57 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 256.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 870.31 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1108.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.91 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9535 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 68827 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 30701 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 406959 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 49247 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9242 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22641 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 62870 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16959 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 16047 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 39903 पॉइंट पर खूलकर, 41190 के उच्च और 39903 के नीचले स्तर को छूकर, 1385 पॉइंट बढ़कर 40400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 15.1 रुपये की बढ़त के साथ 202.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 30.45 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1784.5 रुपये की बढ़त के साथ 9180 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6570 रुपये की बढ़त के साथ 27500.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.93 रुपये की गिरावट के साथ 57 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.13 रुपये की गिरावट के साथ 3.99 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.2 रुपये की गिरावट के साथ 198.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे के सुधार के साथ 26.9 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1045 रुपये की गिरावट के साथ 3067.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1845.5 रुपये की गिरावट के साथ 4378 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 59 पैसे की नरमी के साथ 26.54 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 72 पैसे की नरमी के साथ 10.5 रुपये हुआ।

दिसंबर में इंडिगो को बड़ा झटका बाजार हिस्सेदारी 4 फीसदी घटी

(जीएनएस)। वाशिंगटन। तीन दिनों तक चले आंशिक सरकारी शटडाउन के बाद अमेरिकी संघीय सरकार एक बार फिर कामकाज की पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार दोपहर एक व्यापक खर्च पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही बंद पड़े सरकारी दफ्तर, एजेंसियां और सेवाएं दोबारा सक्रिय हो गईं। ओवल ऑफिस में विधेयक पर दस्तखत करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह समेकित विनियोग अधिनियम पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिससे न केवल सरकार तुरंत खुल गई है, बल्कि वित्त वर्ष के बाकी हिस्से के लिए अधिकांश संघीय विभागों को आवश्यक फंडिंग भी सुनिश्चित हो गई है। इस बयान के साथ ही वाशिंगटन में पिछले कई दिनों से छाई अनिश्चितता और राजनीतिक खींचतान पर अस्थायी विराम लग गया। यह आंशिक शटडाउन बजट और खर्च विधेयकों पर कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण शुरू हुआ था, जिसका असर संघीय कर्मचारियों, सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों पर साफ दिखाई देने लगा था। हजारों कर्मचारी या तो बिना वेतन के काम करने को मजबूर थे या फिर अनिवार्य अवकाश पर भेज दिए गए थे। कई अहम सरकारी सेवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिससे एयरपोर्ट सुरक्षा, आव्रजन प्रक्रिया और आपात सेवाओं पर भी दबाव बढ़ने लगा था। ऐसे माहौल में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को राहत की सांस के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस खर्च पैकेज के जरिए सभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। कानून के तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को केवल अस्थायी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विभाग के लिए फंडिंग की अगली समयसीमा महज दो सप्ताह बाद तय की गई है। इसका मतलब यह है कि यदि इस अवधि के भीतर कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाती, तो एक बार फिर फंडिंग संकट गहरा सकता है और सरकार के कुछ अहम हिस्सों पर ताले लगने की नौबत आ सकती है। इस अस्थायी व्यवस्था ने राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज कर दी है कि मौजूदा समझौता सिर्फ समय खरीदने का प्रयास है, न कि विवादों का स्थायी समाधान। मंगलवार को ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने खर्च विधेयकों के एक समूह को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद आंशिक शटडाउन को खत्म करना और आव्रजन नीति से जुड़े विवादास्पद मुद्दों पर द्विदलीय बातचीत के लिए अतिरिक्त समय जुटाना था। खासतौर पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE की जवाबदेही और उसके अधिकारों को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेताओं के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि समय रहते कोई व्यापक समझौता नहीं होता, तो 14 फरवरी के आसपास एक नया संकट खड़ा हो सकता था, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जैसी अहम एजेंसियां भी बंद होने के कगार पर पहुंच सकती थीं।

हस्ताक्षर से खुला वाशिंगटन का ताला, आंशिक शटडाउन के बाद पटरी पर लौटी अमेरिकी सरकार

(जीएनएस)। वाशिंगटन। तीन दिनों तक चले आंशिक सरकारी शटडाउन के बाद अमेरिकी संघीय सरकार एक बार फिर कामकाज की पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार दोपहर एक व्यापक खर्च पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही बंद पड़े सरकारी दफ्तर, एजेंसियां और सेवाएं दोबारा सक्रिय हो गईं। ओवल ऑफिस में विधेयक पर दस्तखत करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह समेकित विनियोग अधिनियम पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिससे न केवल सरकार तुरंत खुल गई है, बल्कि वित्त वर्ष के बाकी हिस्से के लिए अधिकांश संघीय विभागों को आवश्यक फंडिंग भी सुनिश्चित हो गई है। इस बयान के साथ ही वाशिंगटन में पिछले कई दिनों से छाई अनिश्चितता और राजनीतिक खींचतान पर अस्थायी विराम लग गया।

यह आंशिक शटडाउन बजट और खर्च विधेयकों पर कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण शुरू हुआ था, जिसका असर संघीय कर्मचारियों, सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों पर साफ दिखाई देने लगा था। हजारों कर्मचारी या तो बिना वेतन के काम करने को मजबूर थे या फिर अनिवार्य अवकाश पर भेज दिए गए थे। कई अहम सरकारी सेवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिससे एयरपोर्ट सुरक्षा, आव्रजन प्रक्रिया और आपात सेवाओं पर भी दबाव बढ़ने लगा था। ऐसे माहौल में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को राहत की सांस के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, इस खर्च पैकेज के जरिए सभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। कानून के तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को केवल अस्थायी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विभाग के लिए फंडिंग की अगली समयसीमा महज दो सप्ताह बाद तय की गई है। इसका मतलब यह है कि यदि इस अवधि के भीतर कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाती, तो एक बार फिर फंडिंग संकट गहरा सकता है और सरकार के कुछ अहम हिस्सों पर ताले लगने की नौबत आ सकती है। इस अस्थायी व्यवस्था ने राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज कर दी है कि मौजूदा समझौता सिर्फ समय खरीदने का प्रयास है, न कि विवादों का स्थायी समाधान।

मंगलवार को ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने खर्च विधेयकों के एक समूह को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद आंशिक शटडाउन को खत्म करना और आव्रजन नीति से जुड़े विवादास्पद मुद्दों पर द्विदलीय बातचीत के लिए अतिरिक्त समय जुटाना था। खासतौर पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE की जवाबदेही और उसके अधिकारों को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेताओं के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि समय रहते कोई व्यापक समझौता नहीं होता, तो 14 फरवरी के आसपास एक नया संकट खड़ा हो सकता था, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जैसी अहम एजेंसियां भी बंद होने के कगार पर पहुंच सकती थीं।

फिलहाल ICE और आव्रजन से जुड़ी कई गतिविधियां पिछले वर्ष पारित रिपब्लिकन कर और खर्च कानून के तहत होमलैंड सिक्योरिटी के लिए आवंटित करीब 170 अरब डॉलर की फंडिंग के सहारे चल रही हैं। लेकिन यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं मानी जा रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि वे बिना सुधारों के पूरे साल की फंडिंग को मंजूरी देने के मूड में नहीं हैं। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ICE और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को बड़े बदलाव करने होंगे। उनका कहना है कि यदि इन एजेंसियों के कामकाज और जवाबदेही में सुधार नहीं किया गया, तो पूरे साल का फंडिंग बिल मुश्किल में पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अमेरिकी राजनीति की गहरी ध्रुवीकरण वाली तस्वीर सामने रख दी है, जहां बजट जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी सहमति बनाना कठिन होता जा रहा है। भले ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से फिलहाल शटडाउन खत्म हो गया हो और सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो गया हो, लेकिन आने वाले हफ्तों में कांग्रेस के भीतर होने वाली बातचीत यह तय करेगी कि यह राहत स्थायी साबित होगी या अमेरिका को एक बार फिर सरकारी बंदी के संकट का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल वाशिंगटन में सन्नाटा टूट चुका है, लेकिन राजनीतिक असमंजस अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।